



राज्यों में नीतिआयोग जैसे निकाय

प्रलिस के लयः

नीतऱआयोग, सहकारी संघवाद ।

मेन्स के लयः

राज्यों में नीतऱआयोग जैसे नकऱयों की स्थापना की आवश्यकता और योजना ।

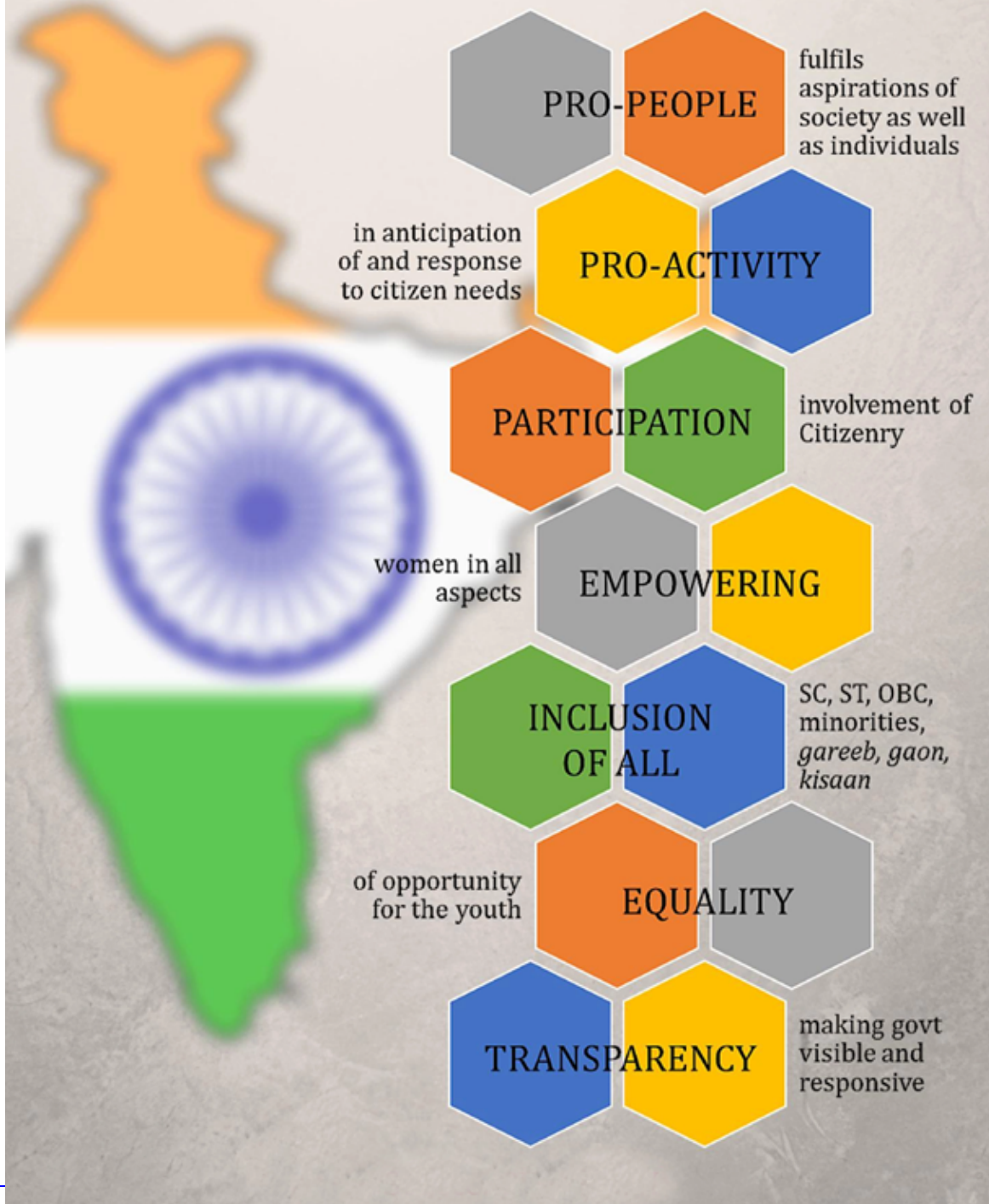
चर्चा में क्यों?

[नीतऱ \(नेशनल इंस्टीटयूशन फॉर ट्रांसफॉर्मगऱ इंडया\) आयोग](#) वर्ष 2017 तक वकऱसतऱ राष्ट्र बनने के दृष्टऱकोण के साथ-साथ तेज़ और समावेशी आर्थऱक वकऱस के लयऱ अपने योजना बोर्डों की जगह समान नकऱयों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य की सहायता करेगा ।

नीतऱआयोग:

- नीतऱआयोग भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनऱक नीतऱथऱकऱ टैक है ।
- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीतऱआयोग द्वारा प्रतऱस्थापतऱ कया गया था, जसऱमें '[सहकारी संघवाद](#)' की भावना को प्रतऱधऱवनतऱ करते हुए **अधऱकऱतम शासन, न्यूनतम सरकार** की परकऱल्पना की परकऱल्पना के लयऱ 'बॉटम-अप' दृष्टऱकोण पर ज़ोर दया गया था ।
- इसके दो हब हैं:
 - टीम इंडया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है ।
 - ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीतऱआयोग के थऱकऱ-टैक की भाँतऱकार्य करता है ।

#NITIaayog is based on the 7 Pillars of Effective Governance



राज्यों में नीतिआयोग जैसे निकाय स्थापति करने की आवश्यकता:

- राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चालक हैं। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धिरक्षा, रेलवे और राजमार्ग जैसे क्षेत्रों को छोड़कर राज्यों की विकास दर का एक समूह है।
 - स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल मुख्य रूप से राज्य सरकार के पास हैं।
- **व्करण में आसानी, भूमिसुधार, बुनियादी ढाँचे के विकास, ऋण प्रवाह और शहरीकरण** में सुधार के लिये राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये सभी नरितर आर्थिक विकास के लिये अनविरय तत्त्व हैं।

- अधिकांश राज्यों ने अब तक अपने योजना विभागों/बोर्डों को फरि से जीवंत करने के लिये बहुत कम कार्य किया है, जो पहले योजना आयोग के साथ काम करते थे और केंद्र के साथ समानांतर राज्य पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करते थे।
 - अधिकांश राज्यों के **नियोजन विभाग, विशाल जनशक्त के साथ लगभग नबिकरयि अवस्था** में हैं और साथ ही कार्य क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी अस्पष्टता है।

कार्यान्वयन के लिये निर्धारित एजेंडा:

- प्रारंभ में इसका लक्ष्य **8-10 राज्यों में मार्च 2023 से पहले ऐसे निकायों की स्थापना** करना है।
 - चार राज्यों अर्थात् **कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम** ने इस संबंध में पहले ही कार्य शुरू कर दिया है।
 - महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है।
- **नीतिआयोग ने इसके लिये एक योजना तैयार की है:**
 - राज्य योजना बोर्डों के मौजूदा ढाँचे की जाँच करने वाली टीमों के निर्माण में सहायता करना।
 - अगले 4-6 महीनों में **स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (SIT)** की स्थापना करना।
 - उच्च गुणवत्ता वाले विश्लेषणात्मक कार्य और नीति सिफारिशों को करने के लिये SIT में पेशवरों की **लेटरल एंट्री** को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य योजना बोर्डों को SIT के रूप में पुनर्गठित करने के अलावा एक बलू-प्रति तैयार किया जाएगा:
 - नीति निर्माण में **राज्यों का मार्गदर्शन** करना।
 - सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की नगिरानी एवं मूल्यांकन।
 - **योजनाओं के वितरण के लिये बेहतर तकनीक या मॉडल का सुझाव देना।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. अटल इनोवेशन मशिन कसि के अंतरगत स्थापति कयि गया है? (2019)

- वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- नीतिआयोग
- कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय

उत्तर: C

व्याख्या:

- अटल इनोवेशन मशिन (AIM) देश की नवाचार और उद्यमशीलता की ज़रूरतों पर वसितृत अध्ययन एवं विचार-विमर्श के आधार पर नवाचार तथा उद्यमता को बढ़ावा देने के लिये नीतिआयोग द्वारा स्थापित प्रमुख पहल है।
- AIM की परकिलपना अंबरेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है जो विभिन्न स्तरों पर नवाचार और उद्यमता के पारस्थितिकी तंत्र की स्थापना तथा संवर्द्धन को प्रोत्साहित करने वाली केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के बीच नवाचार नीतियों के संरेखण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे वजिज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्च शैक्षणिक संस्थान; SME/ MSME उद्योग, कॉर्पोरेट एवं NGO स्तर पर।

अतः विकल्प C सही है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)